

26th of July. The Government of India, however, have not received any request from the B. B. C. to make a documentary film on West Bengal land reforms so far. The Government are ascertaining from the West Bengal Government whether any such preliminary request has come to them. Information asked for is being collected and will be placed on the table of the House in due course.

#### Commercialisation of States in Medical Colleges

1782. SHRI PIUS TIRKEY:

DR. VASANT KUMAR PANDIT:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Health Minister's attention has been drawn to the news appeared in *Indian Express* dated the 8th July, 1981 under caption 'Government to curb sale of medical seats;

(b) if so, how many medical colleges have been found involved in this practice and the details of amount being charged in each case; and

(c) what steps are likely to be taken by Government in future in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKER): (a) to (c). The news item has not been published in the New Delhi edition of the *Indian Express* dated the 8th July, 1981. Efforts are being made to trace the said item in other editions of the Newspaper. As per information available with this Ministry, four medical colleges in Karnataka, which are recognised by the Medical Council of India are charging capitation fees. 65 per cent of the seats in these colleges are free; for allotment to Karnataka students by the Selection Committee constituted by the State Government. In these colleges 5 per cent seats are reserved for candidates from Karnataka who are admitted on payment of

Rs. 60,000/-. 20 per cent seats are meant for external candidates who are admitted on payment of Rs. 1,60,000/- and 10 per cent seats are allotted by the management. In addition, three newly set-up medical colleges in Karnataka and one newly set-up medical college in Andhra Pradesh are also charging capitation fees.

The concerned State Governments will continue to be advised to and the practice of capitation fees.

#### Shortage of Polio Vaccine in the Country

1783. SHRI K. MALLANNA:

SHRI MOHAN LAL PATEL:

SHRI D. P. JADEJA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any shortage of polio vaccine in the country;

(b) whether there is shortage of cold storage facilities in our country in this regard;

(c) whether it is also a fact that this vaccine is not available particularly in the semi-urban and rural areas; and

(d) if so, what efforts are underway to strengthen storage and transportation facilities in the States to achieve increased coverage of rural children by the vaccine?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKER): (a) The Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers who are the nodal Ministry, have reported shortages of imported polio vaccine in the metropolitan cities of Madras and Delhi.

(b) Yes.

(c) Yes. The distribution of polio vaccine is limited to the immunization centres with adequate cold storage facilities.

(d) The Government of India is supplying refrigerators, vaccine carriers, thermocole boxes and dial thermometers to strengthen the cold chain for vaccine in the States. Training course have been organised so that the available resources are used more effectively.

**दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को नियंत्रण में लिया जाना**

1784. श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून 1981 के नवभारत टाइम्स में दिल्ली के जिन कालेजों का प्रबन्ध समितियों ने उन्हें चलाने के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, उनको नियंत्रण में लिए जाने की मांग के बारे में प्रकाशित समाचार की धोर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हा, तो ऐसे कालेजों की संख्या कितनी है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है । .

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शोला कौल) : (क) जी, हा ।

(ख) विश्वविद्यालय को अभी तक किरोड़ीमल तथा जी० डी० सलवान कालेज के प्रबन्ध न्यासियों द्वारा इन कालेजों को चलाने में असमर्थता के कारण इन्हे अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध प्राप्त हुआ है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार के परामर्श से करोड़ोंमल कालेज को सिद्धांत रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेने का निर्णय किया है । ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

जी० डी० सलवान कालेज के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली

प्रशासन अर्द्ध 1983 के पश्चात् इस कालेज को अपने अधिकार में ले लेगा । तब तक यह कालेज अपने वर्तमान प्रबंध द्वारा चलाया जाता रहेगा ।

**खोलोलाबाद (बस्ती) से कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान**

1785. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोक्त रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास की भारी कमी है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेल कर्मचारियों के लिए खोलोलाबाद से गोरखपुर (बस्ती) तक तथा वहां से वापसी के लिए सुबह-शाम दो विशेष गाड़ियां चलानी पड़ती हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार रेल कर्मचारियों की आवास समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खोलोलाबाद (बस्ती) में कालोनी बनाने का है ; और

(घ) यदि हा, तो यह कालोनी कब तक बनाई जायेगी ।

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गोरखपुर मुख्यालय में तैनात लगभग 23.5 प्रतिशत रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी है । इस समय कर्मचारी क्वार्टरों के 104 यूनिट निर्माणाधीन हैं और 1982-83 में 62 अतिरिक्त युनिट क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार किया जा रहा है । जिन रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था नहीं की गयी है, वे